

अ**साधारम्** १४०८५०५०६४ ४ ४

and H--एक्ट 3—उप-खक्ड (ii) FART II---Section 3---Sub-Section (ii) पंतिहरूक स एक्टीबर्क

FURLISHED BY AUTHORITY

ti. 428}

तई दिल्ली, गुझाशर, जुलाई 27, 1990/श्रावण 5, 1912

N . 428] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 1990/SRAVANA 5, 1912

इस भाग भी भिन्न पृथ्ठ संख्या की जाती हो जिससे कि यह अलग संप्रापन के रूप शा राजा जा जरू

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(क्रुंप फ्रांर सहकारिता विचान)

ादिण

नह एउसे 27 जन्ती, 1000

का. आ. 594(आ):— महुष्यस्थ सहन्यंत्र महिनाइ दी श्रीधनियम, 1984 (1984) का 51) की (किंत उपमें इसके प्रवास प्रिक्षायन प्रकृत का है), प्राण 48 की उपनाय (1) में यह उपवाद कि अपे कियी अहुराज सहक्राय का किया की विकास वीडे का अधिकाण किया जाता है। हा बेन्तिय टी द्वार कि ता अन्यक राजावकी की सीमाइटी के कार्यक्रमाण का एक वर्ष से अनुधिक की प्रतिकार की बिवेक पर,

समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु जिसकी कुल श्रयित दो वर्ष से प्रक्षिक नहीं होगी, श्रयंध करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ;

श्रीर नेशनल कोग्रापरेटिव कन्ज्यूमर्स फेंडरेशन श्राफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली की बाबत प्रशासक की नियुक्ति के लिए दो वर्ष की उक्त श्रवधि 14-10-89 की समाप्त हो चुकी थी।

श्रीर भारत सरकार के फमग: का . ग्रा. सं. 796(स्र) तारीख 9 श्रक्तूबर, 1989 श्रीर का. श्रा. 519 (श्र) तारीख 28 जून 1990 द्वारा नेशनल कोप्रापरेटिव कन्ज्यूमर्स फेंडरेशन ग्राफ इण्डिया लिभिटेंड की बाबत श्रिधिनियम की धारा 48की उपधारा (1) के उपबंधों से छूट प्रदान करके प्रशासक की नियुक्ति की श्रवधि को 30-6-90 श्रीर्• 30-7-90 तक बढ़ा दिया गया था;

ग्रीर नागरिक पूर्ति विभाग ने जो नेशनल कोप्रापरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेड का प्रशासनिक विभाग हैं, 31 ग्रगस्त, 1990 तक की ग्रीर श्रवधि के लिए प्रशासक को बनाए रखने की मिकारिण की है, जिसमें कि नेशनल कोग्रापरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेड निवेणक बोर्ड का पुनर्गठन कर सके।

भौर कृषि भौर सहकारिता विभाग नं यह आवश्यक समझा है कि नेशनल कोआ-परेटिब कन्छ्यमर्स फेडरेणन आफ इण्डिया लिगिटेड के निवेशक बोर्ड के निविश्त कराने के प्रयोजन के लिए भ्रधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के उपबंधों से छूट की अविध को 30 जुलाई, 1990 के पण्चात् 31 श्रगस्त, 1990 तक भौर बढ़ाया जाए।

भ्रत: श्रम केन्द्रीय सरकार, भ्रधिनियम की धारा 899 की उपधारा (2) द्वारा प्रयत भिक्तयों का प्रयोग करते हुए नेशनल कों आपरेटिव कन्ज्यूमर्न फैंडरेशन भ्राक दिण्डिया लिमि नई दिल्ली को अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के उपबंधों में उस सीमा तकछूट देती है जिस तक प्रशासक नेशनल को आपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन भ्राक दिण्डिया लिमिटेड, के कार्यकलायों का 31 अनुसा, 1990 तक की और अविधि के लिए प्रबंध करेगा।

[सं. एल ~11011/11/89 एलए**डएम**] प्रालोक भड़तागर, श्वार सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agri. & Cooperation) ORDER

New Delhi, the 27th July, 1990

S.O. 594(E).—Whereas sub-section (1) of section 48 of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the

'Act') provides that where the Board of Directors of a multi-state cooperative society is superseded, the Central Registrar may appoint one or more administrators to manage the affairs of the society for such period not exceeding one year which period may, at the discretion of the Central Registrar, be extended from time to time, so, however, that the aggregate period does not exceed two years;

And whereas, the said period of two years for the appointment of an administrator in respect of National Cooperative Consumers Federation of India Ltd., New Delhi expired on 14-10-89;

And whereas, the period of appointment of the administrator was extended -for a further period upto 30-6-90 and 30-7-90 by granting an exemption from the provisions of sub-section (1) of section 48 of the Act in respect of the National Cooperative Consumers Federation of India Limited as per S.O. No. 796(E) dated 9th October, 1989 of the Government of India and S.O. No. 519(E) dated 28th June, 1990 respectively;

And whereas, the Department of Civil Supplies, the administrative department for the National Cooperative Consumers Federation of India Limited has recommended the continuance of the administrator for a further period upto 31st August, 1990 to enable the National Cooperative Consumers Federation of India Limited to reconstitute the Board of Directors of the National Cooperative Consumers Federation of India Limited.

And whereas, the Department of Agriculture and Cooperation considered it necessary further to extend the period of exemption beyond 30th July, 1990 and upto 31st August, 1990 from the provisions of sub-section (1) of section 48 of the Act for the purpose of holding election to the Board of Directors of the National Cooperative Consumers Federation of India Limited.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Act, the Central Government hereby exempts the National Cooperative Consumers Federation of India Limited, New Delhi from the provisions of sub-section (1) of ection 48 of the Act to the extent that the administrator will manage the affairs of the National Cooperative Consumers Federation of India Limited for a further period upto 31st August, 1990.

> [No. L-11011|11|89-L&M] ALOK BHATNAGAR, Under Secv.